DR. SUBRAMANIAM SWAMY:.. and earlier the Wanchoo Committee and also the 123rd Report of the Public Accounts Committee which has said in a negative sense that tax evasion cannot be removed by the voluntary disclosure scheme. I would like to know from the Minister whether he has given any thought, since his last speech, to the recommendations of these tax-Committees and also the opinion of the Public Accounts Committee on the subject.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Sir, he is a member of the Estimates Committee, and the Estimates Committee is examining income-tax. He cannot ask this question, and it should not be replied to. We have got instructions not to ask questions. A senior Member should not misguide us.

DR SUBRAMANIAM SWAMY: I have asked about the Choksi Committee. I have asked about the Public Accounts Committee...

SHRI R. VENKATARAMAN: I can take care of that.

The question relates to summary assessment....

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: No, it is about tax evasion.

SHRI R. VENKATARAMAN: If you would look into the question, it relates to summary assessments...

MR. SPEAKER: You are right.

SHRI R. VENKATARAMAN: The question that has been put by the hon. Member Dr. Subramaniam Swamy does not relate to summary assessment and, therefore, I am unable to answer.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Please read the Question. Sir, what he says may be in the article, but the Question is about tax evasion. Please read the Question yourself, Sir. If you want to save the Minister, that is a different thing.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: It does refer to summary assessments. I have referred to the newspaper report which talks about summary asssessments.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Tax Evasion.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Tax evasion under Summary Assessment.

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या यह सही है कि इनकम टैक्स की राशि जिन 10 घरानों में बाकी है, उसमें सबसे ज्यादा बकाया में ग्वालियर का राजघराना भी एक है जिसके माननीय सदस्य भी एक सम्मानित सदस्य हैं ?

SHRI R. VENKATARMAN: I want notice.

MR. SPEAKER: Next question—Shri Halder.

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE: Mr. Speaker, Sir...

MR. SPEAKER: Sorry, it is over, Madam.

Mr. Halder—not here. Next question.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

*72. श्री रामावतार शास्त्री :

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक और किश्त दिसम्बर, 1980 से देय हो गई है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की अतिरिक्त महंगाई भत्ते की कितनी किश्तें बकाया हैं; और

(ग) सरकार का विचार ये किस्तें कब तक देने का है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): (a) to (c). An instalment of dearness allowance to the Central Government employees is considered after every 8 point increase in the 12-monthly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers (General) (1960=100). The last instalment of Additional Dearness Allowance was sanctioned to the employees with effect from 1st September, 1980 with reference to the index average of 376. At the end of November, 1980 the index average was 386.66 thus registering a further increase of 8 points. Consequently another instalment of additional dearness allowance to the Central Government employees with effect from 1st December, 1980 has become due for consideration. The question of paying this instalment is under consideration of the Government.

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय 1-12-80 से सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की एक और किस्त बकाया हो गई है और मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार उस पर विचार कर रही है । मंत्री महोदय महंगाई का हाल देख रहे हैं और स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, जोकि 17 तारीख को नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा था कि महंगाई बढ़ नहीं रही है, बल्कि कुछ चीजों की महंगाई में कमी है । मंत्री महोदय स्वीकार कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है और वह सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देना चाहते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार यह जो कनसिडरेशन कर रही है, वह उसका फ़ैसला कब करेगी—क्या जब और ज्यादा महंगाई बढ़ जायेगी, तब करेगी या जल्दी से जल्दी करेगी । मंत्री महोदय कम से कम इसकी कुछ टाइम लिमिट तो बतायें ।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI R. VENKATARAMAN): So far as the first point is concerned, namely, increase in the consumer price index, I am sure the hon. Member, Shri Ramavatar Shastriji knows very well that it is calculated on a twelve monthly average and the increase in prices which occurred last year is being reflected now. We have repeatedly stated that in the year 1979 there has been a very high and steep rise in prices and as a result of that, the average price increase in that year was 19 per cent. Now that is being reflected as we are taking a twelve monthly average and I hope the hon. Member knows that when we say that in this year the increase has been less than in last year, it is not any contradiction when the rise in the consumer price index is calculated for the purpose of payment of Dearness allowance to government servants.

So far as payment of Dearness allowance is concerned, we have to pay and we have accepted the liability. The decision will be taken very soon and, I am sure, much sooner than my friend expects

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, महंगाई भत्ता देने के सम्बन्ध में सरकार की सरकारी कर्मचारियों के संगठनों से, या जे सी एम में, बात होती होगी और सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई न कोई सिद्धान्त निर्धारित किया होगा कि महंगाई बढ़ने पर महंगाई भत्ता कितने दिनों में दिया जायेगा और उसका मोड आफ़ पेमेंट वगैरह क्या होगा । सरकार ने उन लोगों से जरूर कोई समझौता किया है, लेकिन वह उस समझौते को समय पर लागू नहीं करती समय जब बीत जाता है तो उसको लागू करती है जिससे कर्मचारियों को और ज्यादा महंगाई का मुकाबिला करना पड़ता है । तो उनके साथ जो बात हुई है उसको आप स्ट्रिक्टली क्यों नहीं लागू करते ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि

जो महंगाई भत्ता देने का निश्चय किया जाता है उसका प्रभाव पिछले महीनों पर भी पड़ता है, यानी रेट्रोपेक्टिव एफेक्ट भी उसका होता है । इसलिए शासन की यह भावना नहीं है कि पिछला नहीं दिया जायेगा । दो महीने पहले से ड्यू है तो 2 महीने पहले का भी महंगाई भत्ता उनको मिलेगा ।

आल इंडिया एवरेज कन्ज्यूमर प्राइस इंडेक्स की फिगर किसी विशेष महीने को देखने के लिए लेबर ब्यूरो से आंकड़े आते हैं और पिछले महीने के आंकड़े चालू महीने के मध्य में आते हैं, इसलिए इतना समय उसमें लगता है । इसमें शासन की कोई दुर्भावना नहीं है ।

श्री रामावतार शास्त्री : जं सी एम में आपने कोई सिद्धांत लागू किया होगा, वह तो आपने बताया नहीं ।

खेतड़ी कापर के प्रोजेक्ट कार्यालय को कलकत्ता स्थानान्तरित किया जाना

*73. **आचार्य भगवान देव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट के कार्यालय को खेतड़ी से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस कारण परियोजना कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा है ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE) (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

आचार्य भगवान देव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब हमने देखा । गत मास जब हम कलकत्ते में कापर प्रोजेक्ट कार्यालय का संसदीय राजभाषा समिति की तरफ से निरीक्षण करने गए तो जिम्मेदार अधिकारियों ने हमें बताया कि इसका कार्यालय पहले खेतड़ी में था, कुछ समय पूर्व यह कार्यालय यहां लाया गया है । कार्यालय की जो स्थिति हमने देखी और सरकार की जो नीति है उसको सामने रखते हुए हमने विचार किया कि सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो और छोटे-छोटे स्थानों पर इस तरह की सुविधाएं दी जांय जिससे जनता का और सरकार का तथा अधिकारियों का सम्पर्क रहे, तो कलकत्ता में जो कार्यालय खोला गया उसके पीछे सच्चाई क्या है ? यह कार्यालय राजस्थान में पहले था या नहीं और बाद में क्या यह कलकत्ता लाया गया इस की वास्तविकता मंत्री जी बताएंगे । इसके साथ साथ मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार यह कार्यालय जयपुर के अंदर राजस्थान में यदि खोले तो क्या कठिनाई है ? मैं तो इससे भी आगे बढ़ कर जाना चाहता हूं कि जहां पर कापर पैदा होता है वहीं यह कार्यालय सरकार खोले तो अधिकारी और कर्मचारी साथ रह कर उसका विकास कर सकते हैं । खेतड़ी में यह कार्यालय खोला जाय, इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ? सरकार वहां खोलना चाहती है या नहीं ?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, the hon. Member is a little confused with the project itself and the head office of it. So far as the Khetri Copper Project office is concerned, it is already in Khetri and the head office of the Hindustan Copper Limited was shifted in 1973—not now—to Calcutta. After that two or three other copper complexes were also brought within the purview of the H. C. L. one in Ghatshila in Bihar and the other in Malanjkhand in Madhya Pradesh. It was thought that the head office should be there. So